



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 721]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 8, 2000/कार्तिक 17, 1922

No. 721]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 2000/KARTIKA 17, 1922

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बीमा प्रभाग)

अधिसूचना

नई फ़िल्मी, 3 नवम्बर, 2000

का. आ. 995(अ).—केन्द्रीय सरकार भारतीय साधारण बीमा निगम को “भारतीय पुनर्बीमांक” के रूप में अपनी निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101ए(8)(ii) के अन्तर्गत भारत में पुनर्बीमा व्यवसाय कार्यान्वयन करने के लिए एतद्वारा अनुमोदन करती है।

[मि. सं. 8 (31)/2000-बीमा-VI]

अजित एम. शरण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Insurance Division)
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2000

S.O. 995 (E).—In exercise of the powers vested with the Central Government under Section 101A(8)(ii) of the Insurance Act, 1938, the Central Government hereby approves General Insurance Corporation of India as the “Indian Reinsurer” to carry on reinsurance business in India.

[F. No. 8/31/2000-Ins.-VI]

AJIT M. SHARAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2000

का. आ. 996(अ).—साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा वित्त मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 29 दिसम्बर, 1972 के का.आ. 770 (अ) को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है, बशर्ते कि ऐसा निरसन उक्त अधिसूचना के पूर्ववर्ती प्रधालन अथवा उसके अन्तर्गत विधिवत किए गए अध्या द्वारा किसी प्रधालन को प्रभावित नहीं करेगा।

[फा. सं. 8 (31)/2000-बीमा-VI]

अजित एम. शरण, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2000

S.O. 996(E).—In exercise of the powers conferred by Section 35 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O. 770 (E), dated the 29th December, 1972 with immediate effect provided that such rescission shall not affect the previous operation of the said notification or any thing duly done or suffered thereunder.

[F. No. 8/31/2000-Ins.-VI]

AJIT M. SHARAN, Jt. Secy.